Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

23 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. भारत सरकार ने भारत-AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए लोगो और प्रमुख पहलों का अनावरण किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में भारत-AI इम्पैक्ट समिट 2026 के आधिकारिक लोगो और प्रमुख पहलों का अनावरण किया। यह समिट 19-20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया।

- **यह शिखर सम्मेलन पहली बार है जब कोई वैश्विक दक्षिण देश वैश्विक AI कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, जो जिम्मेदार और समावेशी AI विकास में भारत के नेतृत्व पर जोर देगा।**

- **भारत ने IndiaAI मिशन के तहत अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को 10,000 GPUs से बढ़ाकर 38,000 GPUs कर दिया है। इसके अतिरिक्त, देश भर में 570 AI डेटा लैब स्थापित करने की योजना है, जिनमें से 30 इंटेल के सहयोग से पहले ही समर्पित हो चुकी हैं।**

- **प्रमुख पहलों में UDAAN - ग्लोबल AI पिच फेस्ट, YuvaAI इनोवेशन चैलेंज, AI बाय HER, ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज, रिसर्च सिम्पोजियम और भारत तथा 30 से अधिक देशों के 300 से अधिक प्रदर्शकों के साथ AI एक्सपो शामिल हैं।**

Key Points:-

(i) बहुभाषी AI, स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान को लक्षित करते हुए भारत जेन (IIT बॉम्बे), फ्रैक्टल एनालिटिक्स रीजनिंग मॉडल, टेक महिंद्रा इंडिक मॉडल, जेनलूप का 22-भाषा मॉडल और इंटेलीहेल्थ का EEG AI मॉडल सहित आठ स्वदेशी AI फाउंडेशनल मॉडल परियोजनाओं की घोषणा की गई।

(ii) IndiaAI फेलोशिप कार्यक्रम का विस्तार 13,500 विद्वानों (8,000 UG, 5,000 PG, 500 PhD) को समर्थन देने के लिए किया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कानून जैसे विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें डेटा एनोटेशन और क्यूरेशन पर नए कौशल मॉड्यूल शामिल हैं।

(iii) शिखर सम्मेलन की रूपरेखा तीन सूत्रों - लोग, ग्रह और प्रगति - और सात चक्रों पर आधारित है, जो मानव पूंजी, सामाजिक सशक्तिकरण, विश्वसनीय AI, लचीलापन, विज्ञान, संसाधनों का लोकतंत्रीकरण और सामाजिक भलाई के लिए AI पर केंद्रित है।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और AYUSH मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए 5.26 करोड़ रुपये की एकीकृत पुनर्वास परियोजनाएं शुरू कीं।

सितंबर 2025 में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPWD) ने दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए एकीकृत पुनर्वास पहल शुरू करने हेतु आयुष मंत्रालय के साथ साझेदारी की। इन परियोजनाओं को नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष की 19वीं शासी निकाय बैठक के दौरान मंजूरी दी गई, जिसकी अध्यक्षता DEPWD के सचिव राजेश अग्रवाल ने की।

• आयुष चिकित्सा पद्धति को आधुनिक उपचारों के साथ जोड़ने वाली पुनर्वास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत कुल 5.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

• यह पहल चार राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से की जाएगी: NIEPID (सिकंदराबाद, तेलंगाना); SVNIRTAR (ओडिशा); AYJNISHD (मुंबई, महाराष्ट्र); और PDUNIPPD (नई दिल्ली)।

• NIEPID में न्यूरोडायवर्सिटी पर शोध के लिए एक आयुष केंद्र स्थापित किया जाएगा। SVNIRTAR में रक्त विकारों के प्रबंधन के लिए रक्तामृत वटी (आयुर्वेदिक सूत्रीकरण) का परीक्षण किया जाएगा।

Key Points:-

(i) AYJNISHD श्रवण बाधित छात्रों और उनके परिवारों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर योग-आधारित अध्ययन आयोजित करेगा।

(ii) PDUNIPPD घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए पंचकर्म बनाम फिजियोथेरेपी की तुलना करेगा, मधुमेह चिपकने वाले कैप्सूलाइटिस के लिए हर्बल उपचार बनाम इंसुलिन का मूल्यांकन करेगा, और वृद्ध वयस्कों के लिए व्यावसायिक चिकित्सा के साथ योग को एकीकृत करेगा।

(iii) यह सहयोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और संयुक्त राष्ट्र के स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (2021-2030) के अनुरूप है, जो समावेशी और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

3. पीयूष गोयल ने औद्योगिक पार्कों की पहचान करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए IPRS 3.0 का शुभारंभ किया।

सितंबर 2025 में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के दशक भर चलने वाले समारोह के दौरान नई दिल्ली में औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS) 3.0 का शुभारंभ किया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से विकसित इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक पार्कों को मानक बनाना और भारत के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है।

• IPRS 3.0 पूरे भारत में औद्योगिक पार्कों की सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन और बेंचमार्क करेगा, जिससे हितधारकों को बुनियादी ढांचे में सुधार और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय डेटा उपलब्ध होगा।

• 2018 में पायलट चरण और 2021 में IPRS 2.0 के आधार पर, नए संस्करण में अधिक समग्र मूल्यांकन के लिए स्थिरता, हरित बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स

कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, कौशल लिंकेज और किरायेदार फीडबैक जैसे मापदंडों को शामिल किया गया है।

Key Points:-

(i) IPRS 3.0 के तहत, औद्योगिक पार्कों को अग्रणी, चुनौती देने वाले और आकांक्षी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और लक्षित हस्तक्षेपों में नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन होगा।

(ii) इस पहल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पार्कों को प्रदर्शित करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने और अपने औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत एक टिकाऊ, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी निवेश केंद्र बन सकेगा।

INTERNATIONAL

1. पीयूष गोयल ने व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MoC&I) ने 18-19 सितंबर, 2025 को व्यापार और निवेश संबंधों को मज़बूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का दौरा किया। उनके साथ CII, FICCI और ASSOCHAM का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बड़ा भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी था, जो शिक्षा, प्रौद्योगिकी और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित था।

• यात्रा के दौरान, पीयूष गोयल ने अबू धाबी, UAE में आयोजित अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान के साथ निवेश पर 13वें भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल (HLJTFI) की सह-अध्यक्षता की।

• HLJTFI ने प्रमुख ढांचे पर प्रगति की समीक्षा की, जिसमें भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), जो मई 2022 में लागू हुआ, दोहरे कराधान संधि (DTT), और दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच चल रहे सहयोग शामिल हैं।

Key Points:-

(i) पीयूष गोयल ने अबू धाबी में UAE के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी के साथ यूएई-भारत व्यापार परिषद (UIBC) गोलमेज सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी की।

(ii) दोनों राष्ट्रों ने अगले तीन वर्षों के भीतर गैर-तेल, गैर-कीमती धातुओं के द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे पारंपरिक क्षेत्रों से परे व्यापार में विविधता लाने के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया गया।

(iii) भारत और UAE ने आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और गहरा करने के लिए समुद्री, अंतरिक्ष, रक्षा, एयरोस्पेस, डेटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, कपड़ा, चमड़ा और गृह सज्जा सहित सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की।

2. सिंगापुर में 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को 2025-29 के लिए INTERPOL एशियाई समिति का सदस्य चुना गया।

सितंबर 2025 में, भारत को 2025-29 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL) की एशियाई समिति का सदस्य चुना गया। 18-19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर स्थित इंटरपोल ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोवेशन (IGCI) में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से स्वीकृत यह उपलब्धि, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग में भारत की भूमिका को और मज़बूत करेगी।

• भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो-भारत (NCB-भारत) के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया।

• INTERPOL एशियाई समिति में भारत की सदस्यता 2025 से 2029 तक है। एक सदस्य के रूप में, भारत एशिया भर में कानून प्रवर्तन प्राथमिकताओं पर सलाह देने, समीक्षा करने और समन्वय करने में सक्रिय रूप से भाग लेगा, तथा इस क्षेत्र के भीतर रणनीतिक और परिचालन पहलों को आकार देगा।

• समिति संगठित अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी सहित गंभीर अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने को प्राथमिकता देती है। भारत की भागीदारी से इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सहयोगात्मक ढाँचे और परिचालन समन्वय में वृद्धि होने की उम्मीद है।

Key Points:-

(i) यह समिति एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती है, चर्चाओं को सुगम बनाती है और क्षेत्रीय कानून प्रवर्तन मुद्दों पर विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह एशिया के 53 सदस्य देशों के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान करती है और पुलिस सहयोग में सुधार हेतु समन्वित कार्यों का मार्गदर्शन करती है।

(ii) भारत का चुनाव उसकी अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन उपस्थिति को मजबूत करता है, जिससे क्षेत्रीय नीतियों को आकार देने, खुफिया जानकारी साझा करने और सहयोगात्मक पहल को आगे बढ़ाने में अधिक प्रभाव प्राप्त होता है।

(iii) यह सदस्यता उभरते अंतरराष्ट्रीय अपराध चुनौतियों का जवाब देने और वैश्विक सुरक्षा नेटवर्क को सुदृढ़ करने के भारत के प्रयासों को भी बढ़ावा देगी।

3. विश्व व्यापार संगठन ने विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें 2040 तक वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में AI की क्षमता पर प्रकाश डाला गया।

सितंबर 2025 में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने स्विट्जरलैंड में WTO पब्लिक फोरम के दौरान अपनी वार्षिक विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 (WTR) जारी की, जिसका शीर्षक था "व्यापार और AI को सभी के लाभ के लिए एक साथ काम करना"। यह रिपोर्ट वैश्विक व्यापार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की परिवर्तनकारी भूमिका का आकलन करती है और 2040 तक व्यापार में 40% तक की वृद्धि और महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ का अनुमान लगाती है।

• विश्व व्यापार संगठन (WTR) 2025 का अनुमान है कि AI 2040 तक वैश्विक व्यापार में 34-37% की वृद्धि कर सकता है, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में होने की उम्मीद है। AI अपनाने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 12-13% की वृद्धि होने की भी उम्मीद है, जबकि AI का उपयोग करने वाली लगभग 90% कंपनियाँ प्रत्यक्ष व्यापार लाभ और 56% बेहतर व्यापार जोखिम प्रबंधन की रिपोर्ट करती हैं।

• अनुमान है कि AI कुल कारक उत्पादकता (TFP) में वार्षिक वृद्धि को लगभग 0.68 प्रतिशत अंकों तक बढ़ा देगा। टीएफपी यह मापता है कि कोई अर्थव्यवस्था श्रम और पूंजी जैसे इनपुट का कितनी कुशलता से उपयोग करती है, जो आर्थिक दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने में एआई की क्षमता को उजागर करता है।

• विश्व व्यापार संगठन के अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए एआई अपनाने के कई परिदृश्यों का मॉडल तैयार किया है। बेंचमार्क परिदृश्य में, निम्न-आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ (LIE) उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं (HIE) से पीछे हैं, जहाँ LIE के लिए अनुमानित आय वृद्धि 8%, मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं (MIE) के लिए 11% और HIE के लिए 14% है। LIE में डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार या व्यापक रूप से AI अपनाने से निम्न और मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 11-15% तक बढ़ सकती है।

Key Points:-

(i) 2023 में, कच्चे माल, अर्धचालकों और मध्यवर्ती इनपुट सहित AI-सक्षम वस्तुओं का वैश्विक व्यापार 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का था। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि डिजिटल सेवाओं के व्यापार में 10% की वृद्धि विभिन्न देशों में AI पेटेंट उद्धरणों में 2.6% की वृद्धि से जुड़ी है, जो डिजिटल व्यापार और नवाचार के बीच संबंध को रेखांकित करता है।

(ii) AI को अपनाने में असमानता बनी हुई है, जहाँ केवल 41% छोटी कंपनियाँ ही AI का उपयोग करती हैं, जबकि 60% से ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ AI का उपयोग करती हैं। निम्न और निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक-तिहाई से भी कम कंपनियाँ AI का उपयोग करती हैं, जो तकनीक तक पहुँच और इसके आर्थिक लाभों में असमानताओं को उजागर करता है।

(iii) AI-संबंधित उत्पादों के लिए वैश्विक सब्सिडी 15% से अधिक हो गई है, जिसमें 98% से अधिक उच्च और उच्च-मध्यम आय वाले देशों से आ रही है, जिससे एआई क्षमताओं के केंद्रित होने का जोखिम बढ़ रहा है। AI-संबंधित वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जो 2012 में 130 से बढ़कर 2024 में लगभग 500 हो गई है, और कुछ LIE में AI-सक्षम वस्तुओं पर बाध्य शुल्क 45% तक पहुँच गए हैं, जो खुली और पूर्वानुमानित व्यापार नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है।

BANKING & FINANCE

1. पेरुपी ने एकीकृत सीमा-पार भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए BRISKPE के साथ साझेदारी की।

एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करती है।

2. फोनपे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली।

सितंबर 2025 में, भारत की अग्रणी फिनटेक कंपनियों में से एक, वॉलमार्ट समर्थित फोनपे लिमिटेड (पूर्व में फोनपे प्राइवेट लिमिटेड) को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अंतिम मंजूरी मिली। यह नियामक उपलब्धि फोनपे को लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने व्यापारी नेटवर्क का विस्तार करने में सक्षम बनाती है।

- **भुगतान एग्रीगेटर के रूप में RBI की मंज़ूरी के साथ, फ़ोनपे अब बड़ी संख्या में व्यापारियों, खासकर SMEs को अपने साथ जोड़ सकेगा। इससे उन व्यवसायों तक डिजिटल भुगतान समाधानों की पहुँच बढ़ेगी जो पहले कम पहुँच पाते थे, और वित्तीय समावेशन में मौजूद कमियों को दूर किया जा सकेगा।**

- **नियामकीय मंज़ूरी से फ़ोनपे को भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की स्थिति मिलेगी। सुलभ, कुशल और सुरक्षित भुगतान समाधान प्रदान करके, कंपनी**

सितंबर 2025 में, अग्रणी सॉफ्टवेयर विकास कंपनी पेरुपी ने क्रॉस-बॉर्डर भुगतान सेवाओं को बढ़ाने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने वाला एक एकीकृत वैश्विक भुगतान मंच प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर (PA-CB) BRISKPE के साथ साझेदारी की।

- **PayRupy-BRISKPE साझेदारी का उद्देश्य घरेलू और सीमा पार भुगतान दोनों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करना है।**

- **यह सहयोग भारतीय व्यवसायों, फ्रीलांसरों, निर्यातकों और व्यक्तियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है, जिससे निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन संभव हो पाता है।**

Key Points:-

(i) PA-CB (पेमेंट एग्रीगेटर - क्रॉस बॉर्डर) मॉडल का उपयोग करते हुए, यह प्लेटफ़ॉर्म स्केलेबल और कुशल क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। इसे छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs), बड़े उद्यमों, निर्यातकों और फ्रीलांसरों की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विश्वसनीय, तेज़ और उपयोगकर्ता-अनुकूल वैश्विक भुगतान समाधान प्रदान करता है।

(ii) पेरुपी की घरेलू भुगतान विशेषज्ञता को ब्रिस्कपे के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जोड़कर, यह साझेदारी

छोटे व्यवसायों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सशक्त बनाएगी।

Key Points:-

(i) इस अनुमोदन से फोनपे को अपनी भुगतान गेटवे सेवाओं का विस्तार करने की अनुमति मिल गई है, जिसमें तत्काल व्यापारी ऑनबोर्डिंग, डेवलपर-अनुकूल एकीकरण और सुचारू चेकआउट अनुभव जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ii) भुगतान एग्रीगेटर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है जो व्यापारियों को अलग-अलग भुगतान गेटवे सेटअप की आवश्यकता के बिना डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है।

(iii) RBI ढांचा सभी डिजिटल भुगतान मध्यस्थों के लिए उपभोक्ता संरक्षण, सुरक्षित प्रसंस्करण और परिचालन पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

ECONOMY & BUSINESS

1. HCL और OIL ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के अन्वेषण और विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज सोर्सिंग में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने तांबा और संबंधित खनिजों सहित महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए सहयोग करने हेतु 19 सितंबर, 2025 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

• खान मंत्रालय के अधीन एक मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तांबे और संबंधित उत्पादों के खनन, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में संलग्न है। कंपनी वर्तमान में तांबे के अयस्क के खनन और संवर्धन तथा तांबे के सांद्रण की बिक्री पर केंद्रित है।

• ऑयल इंडिया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, एक प्रमुख एकीकृत तेल और गैस कंपनी है, जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास, उत्पादन और परिवहन में सिद्ध विशेषज्ञता रखती है।

• महत्वपूर्ण खनिजों के बढ़ते महत्व को समझते हुए, ओआईएल ने अपने मुख्य ऊर्जा पोर्टफोलियो को पूरक बनाने के लिए इस क्षेत्र में विविधता लायी है।

Key Points:-

(i) HCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह और ऑयल इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. रंजीत रथ तथा दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान-प्रदान किया गया।

(ii) HCL और OIL के बीच सहयोग भारत की खनिज सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

(iii) भारत सरकार के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप, यह साझेदारी देश की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और तकनीकी उन्नति के लिए आवश्यक रणनीतिक खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

MOUs and Agreement

1. IIM उदयपुर ने भारत के डेटा और AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग और भाषाई सहयोग पर हस्ताक्षर किए।

सितंबर 2025 में, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) उदयपुर, राजस्थान ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), नीति आयोग और भाषाई अनुसंधान संस्थान (BRI) के साथ रणनीतिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य डेटा विश्लेषण, निगरानी एवं मूल्यांकन, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की क्षमताओं को मज़बूत करना है, जिसमें IIM उदयपुर एक प्रमुख शैक्षणिक और ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करेगा।

- **IIM उदयपुर ने सांख्यिकीय चुनौतियों का समाधान करने और उन्नत डेटा विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग के तहत, IIM उदयपुर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की डेटा इनोवेशन लैब के लिए एक ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करेगा और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सहायता करेगा।**

- **संस्थान ने मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और टूलकिट तैयार करने हेतु नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) के साथ एक आशय पत्र (SoI) पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने विकास नीति एवं प्रबंधन केंद्र (CDPM) के माध्यम से, IIM उदयपुर भारत के निगरानी एवं मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करेगा।**

Key Points:-

(i) अनुसंधान मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत, IIM उदयपुर ने क्षेत्रीय केंद्रों के निर्माण और कम प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं के लिए डेटासेट को समृद्ध करने के लिए भारत के राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, भाषिनी के साथ साझेदारी की।

(ii) यह सहयोग भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक समावेशी बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

(iii) भाषिनी साझेदारी IIM उदयपुर को AI और भाषा प्रौद्योगिकियों में छात्रों को कुशल बनाने, बहुभाषी अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक, शासन और तकनीकी डोमेन में भारत के AI पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने में सक्षम बनाएगी।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. ACC ने प्रवीण कुमार को ITBP का महानिदेशक और प्रवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त करने को मंजूरी दी।

सितंबर 2025 में, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक (DG) और प्रवीर रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के गृह मंत्रालय (MoHA) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

• 1993 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IPS अधिकारी प्रवीण कुमार को ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर 2025 को राहुल रसगोत्रा (IPS) के सेवानिवृत्त होने पर पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2030 तक रहेगा।

• AGMUT कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेश) के 1993 बैच के IPS अधिकारी प्रवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सीआईएसएफ में विशेष महानिदेशक (SDGs) के पद पर कार्यरत, वह 30 सितंबर 2025 को राजविंदर सिंह भट्टी (IPS) का स्थान लेंगे और उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2029 तक रहेगा।

• प्रवीण कुमार वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जबकि प्रवीर रंजन CISF में विशेष महानिदेशक (SDG) के रूप में कार्यरत हैं, जो कानून प्रवर्तन और सुरक्षा प्रबंधन में उनकी वरिष्ठ-स्तर की विशेषज्ञता को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) ये नियुक्तियाँ भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने की सरकार की रणनीति के अनुरूप हैं। आईटीबीपी भारत-चीन सीमा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि CISF महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे, उद्योगों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

(ii) भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2025) के अवसर पर, सीआईएसएफ को 32 पदक प्राप्त हुए, जिनमें विशिष्ट सेवा के लिए 3 राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए 26 पदक शामिल हैं। ITBP को 13 पदक प्रदान किए गए, जिनमें विशिष्ट सेवा के लिए 3 राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए 10 पदक शामिल हैं।

(iii) इन नेतृत्व परिवर्तनों के साथ, ITBP और CISF दोनों को सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने में रणनीतिक दिशा प्राप्त होने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

SPORTS

1. भारतीय तीरंदाजी संघ ने राम चरण को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर तीरंदाजी प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया।

सितंबर 2025 में, भारतीय तीरंदाजी संघ (AAI) ने आर्चरी प्रीमियर लीग (APL) की शुरुआत की। इसका पहला सत्र 2–12 अक्टूबर 2025 तक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित होगा। यह लीग भारत में तीरंदाजी की लोकप्रियता बढ़ाने और भविष्य के ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए शुरू की गई है।

• शुरुआती कार्यक्रम में AAI ने आधिकारिक एंथम और प्रोमोशनल वीडियो जारी किया तथा अभिनेता और फिल्म निर्माता राम चरण को आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एंबेसडर घोषित किया।

• APL को विश्व तीरंदाजी (WA) और एशियाई तीरंदाजी महासंघ (AAF) का समर्थन प्राप्त है, तथा यह भारत सरकार की प्रतिभा खोज पहल और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के साथ मिलकर जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तरीय भागीदारी को मजबूत करता है।

• पहले सत्र में कुल 6 फ्रेंचाइज़ी टीमें होंगी, जिनमें 48 तीरंदाज (36 भारतीय और 12 अंतरराष्ट्रीय) भाग लेंगे। प्रत्येक टीम में 8 सदस्य (4 पुरुष और 4 महिलाएं) होंगे, जिनमें अधिकतम 2 विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं।

Key Points:-

(i) भाग लेने वाली टीमें हैं: चोला चीफ्स (तमिलनाडु), पृथ्वीराज योद्धास (दिल्ली), माइटी मराठा (महाराष्ट्र), काकतीय नाइट्स (तेलंगाना), राजपुताना रॉयल्स (राजस्थान) और चेरो आर्चर्स (झारखंड)।

(ii) APL डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें मैच ओलंपिक मानक दूरी पर होंगे — रिकर्व के लिए 70 मीटर और कंपाउंड के लिए 50 मीटर। एक विशेष पहलू यह है कि पहली बार रिकर्व और कंपाउंड के मिश्रित संयुक्त दल एक साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे।

(iii) APL का उद्देश्य भारतीय तीरंदाजों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव दिलाना, भारत में तीरंदाजी की वैश्विक पहचान को बढ़ावा देना और 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक (अमेरिका) तथा 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक (ऑस्ट्रेलिया) की तैयारी करना है।

AWARDS

1. हिंदी ड्रामा 'होमबाउंड' को 98वें ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया।

सितंबर 2025 में, नीरज घायवान द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की ड्रामा होमबाउंड को आधिकारिक तौर पर 98वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया था।

• फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में फिल्म निर्माता एन. चंद्रा की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय जूरी के साथ चयन की घोषणा की।

• "होमबाउंड" बशारत पीर के 2020 के न्यूयॉर्क टाइम्स निबंध "टेकिंग अमृत होम" से प्रेरित है। यह फिल्म ग्रामीण उत्तर भारत के दो दोस्तों की यात्रा को दर्शाती है जो जाति और सांप्रदायिक बाधाओं को पार करने के लिए पुलिस की नौकरी की तलाश में हैं।

• इसमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सूरत, गुजरात से उत्तर प्रदेश तक की उनकी पैदल यात्रा को दर्शाया गया है, जो विपरीत परिस्थितियों के बीच उनके लचीलेपन पर प्रकाश डालता है।

Key Points:-

(i) इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों के अभिनय को उनकी प्रामाणिकता और भावनात्मक गहराई के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया, जिससे

फिल्म को फेस्टिवल में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

(ii) होमबाउंड का प्रीमियर कान्स 2025 में अन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुआ, जहाँ इसे नौ मिनट तक खड़े होकर तालियाँ बजाई गईं। इसने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF 2025) में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में दूसरा रनर-अप भी हासिल किया, जिससे इसे वैश्विक स्तर पर अच्छी सराहना मिली।

(iii) इस फिल्म ने मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव (IFFM 2025) में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोनों पुरस्कार जीते। ये सम्मान इसकी कलात्मक उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा के सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाते हैं।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व जल निगरानी दिवस 2025 विश्व स्तर पर 18 सितंबर को मनाया गया।

जल गुणवत्ता के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने, जल संसाधनों की सुरक्षा में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और सतत जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए 18 सितंबर को दुनिया भर में विश्व जल निगरानी दिवस (WWMD) 2025 मनाया गया।

• WWMD की स्थापना 2003 में अमेरिकन क्लीन वाटर फ़ाउंडेशन (ACWF) द्वारा एक वैश्विक शैक्षिक पहल के रूप में की गई थी। इसका पहला आयोजन 18 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वच्छ जल अधिनियम, 1972 के अनुरूप हुआ था।

• प्रारंभ में 18 अक्टूबर को मनाया जाने वाला WWMD की तिथि 2007 में आधिकारिक तौर पर बदलकर 18 सितम्बर कर दी गई, ताकि अक्टूबर में स्कूल बंद होने से पहले व्यापक वैश्विक भागीदारी, विशेष रूप से छात्रों के बीच, को शामिल किया जा सके।

• बाद में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर अर्थइको वाटर चैलेंज (EEWC) कर दिया गया, जिसे पहले विश्व जल निगरानी चुनौती (WWMC) के नाम से जाना जाता था, ताकि जल संरक्षण और सतत उपयोग में सार्वजनिक सहभागिता और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

Key Points:-

(i) 2006 में, WWMD का समन्वय ACWF से जल पर्यावरण महासंघ (WEF) और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ (IWA) को सौंप दिया गया। बाद में 2015 में, पर्यावरण संबंधी गैर-लाभकारी संस्था, अर्थइको इंटरनेशनल ने समन्वय का कार्यभार संभाला।

(ii) अर्थइको वाटर चैलेंज प्रतिवर्ष 22 मार्च (विश्व जल दिवस) से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह युवाओं और सामुदायिक वैज्ञानिकों को जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने, वैश्विक स्तर पर परिणाम साझा करने और सुरक्षात्मक उपायों की वकालत करने में सक्षम बनाता है।

(iii) वाटर चैलेंज एम्बेसडर प्रोग्राम के माध्यम से, अर्थइको इंटरनेशनल 14-22 वर्ष की आयु के युवा नेताओं को स्थानीय जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित और समर्थित करता है। 2025 में, 43 नए एम्बेसडर चुने गए, जो 11 नए युवा नेताओं के साथ मिलकर एक और वर्ष तक अपना प्रभाव जारी रखेंगे।

2. संयुक्त राष्ट्र (UN) 20 सितंबर, 2025 को विश्व सफाई दिवस मनाया ।

संयुक्त राष्ट्र (UN) वैश्विक स्वच्छता प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 20 सितंबर को विश्व स्वच्छता दिवस मनाता है। 2025 में मनाया जाने वाला यह दिवस कपड़ा और फैशन अपशिष्ट की तेज़ी से बढ़ती समस्या से निपटने पर ज़ोर देता है।

• 8 दिसंबर 2024 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रस्ताव A/RES/78/122 को अपनाया, जिसके तहत 20 सितंबर को आधिकारिक तौर पर विश्व सफाई दिवस घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम (UN-Habitat) इस आयोजन को सुगम बनाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सभा द्वारा 9 जून 2023 को पारित प्रस्ताव 2/3 की सिफ़ारिश के बाद, पहला आयोजन 18 सितंबर 2024 को हुआ।

• 2025 के इस दिवस का लक्ष्य कपड़ा और फ़ैशन अपशिष्ट है, जो एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। वैश्विक स्तर पर, फ़ैशन उद्योग सालाना लगभग 92 मिलियन टन कपड़ा अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसका अधिकांश भाग लैंडफिल में चला जाता है या जला दिया जाता है, जिससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है।

• दक्षिण एशिया के लिए प्लास्टिक मुक्त नदियां और समुद्र (प्लीज) पहल, विश्व बैंक (WB) के समर्थन से दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी) के नेतृत्व में, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और सामग्री के उपयोग में टिकाऊ उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए काम करती है।

Key Points:-

(i) भारत खुले में शौच को समाप्त करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए या स्वच्छ भारत मिशन) जैसे अभियानों के माध्यम से सक्रिय रूप से भाग लेता है।

(ii) भारत खुले में शौच को खत्म करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान (SBA या स्वच्छ भारत मिशन) जैसे अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, नागरिकों को समुद्र तटों और समुद्री वातावरण को स्वच्छ रखने में शामिल करता है।

(iii) 2022 में शुरू किया गया स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर (स्वच्छ तट, सुरक्षित समुद्र) अभियान 75 भारतीय समुद्र तटों को कवर करता है, जबकि नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र संवाद और सामुदायिक सफाई जैसे वैश्विक कार्यक्रम प्रदूषण और कपड़ा अपशिष्ट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रकाश डालते हैं।

Static GK

Ministry of AYUSH	मंत्री: श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव	मुख्यालय: नई दिल्ली
UAE	राजधानी: अबू धाबी	प्रधान मंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
International Criminal Police Organization (INTERPOL)	महासचिव : वाल्डेसी उर्कीज़ा (ब्राज़ील)	अध्यक्ष : अहमद नासर अल-रईसी (संयुक्त अरब अमीरात, यूएई)
World Trade Organisation (WTO)	महानिदेशक (DG) : न्गोजी ओकोन्जो-इवेला	मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
Ministry of Home Affairs (MHA)	केंद्रीय मंत्री: अमित शाह	मुख्यालय: नई दिल्ली
Archery Association of India(AAI)	अध्यक्ष : अर्जुन मुंडा	मुख्यालय: नई दिल्ली
EarthEcho International	अध्यक्ष : फिलिप कॉस्ट्यू	मुख्यालय : वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)	कार्यकारी निदेशक (ED) : एनाक्लौडिया रोसबैक	मुख्यालय : नैरोबी, केन्या